भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1634

गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

खाड़ी देशों के लिए उड़ान सेवाएँ

1634. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल विमानपत्तनों और जीसीसी देशों के बीच उड़ान सेवाओं में वर्तमान मांग-आपूर्ति अंतर से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों के पूर्ण कोटे का उपयोग करते हुए केरल के प्रमुख विमानपत्तनों से जीसीसी देशों के विभिन्न गंतव्यों तक सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उड़ान संपर्क बढ़ाने और केरल से प्रवासी समुदाय के लिए हवाई यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए एयरलाइनों और जीसीसी देशों के साथ पहल करने या बातचीत करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालन भारत और संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा शासित होते हैं। हवाई सेवा समझौते के अनुसार, भारतीय नामित वाहक पारस्परिक रूप से सहमत क्षमता सीमाओं के अनुसार गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों सहित किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से/के लिए विदेशी गंतव्यों हेतु परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में एक प्वाइंट ऑफ कॉल से प्रचालन कर सकती है यदि इसे एएसए में एक प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में नामित किया गया हो। भारत में किसी भी स्थान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करना यात्री मांग, स्लॉटों की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर पूर्ण रूप से अनुसूचित एयरलाइनों का व्यावसायिक निर्णय है। सरकार नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करती है, लेकिन एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है।

हवाई क्षमता पात्रताओं का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत और अन्य देशों के बीच हवाई सेवाओं पर समय-समय पर हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है, जो भारतीय विमानन क्षेत्र को होने वाले लाभ, उस देश में भारतीय प्रवासियों की

उपस्थिति, भारतीय वाहकों की भविष्य की योजनाओं, पारस्परिकता के तत्व, लाभों के संतुलन और दो देशों के बीच अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करता है।

*****